मार्च 2021
खंड - XXXVII | अंक - I

# एक्ज़िमिअस:
# निर्यात लाभ

## इस अंक में


- विकास सहयोग बढ़ाने के लिए काउंटरट्रेड रणनीति
- भारत में डिजिटल विनिर्माण
- भारत–जापान व्यापार संबंध
- भारतीय कोयला क्षेत्र और कोयला व्यापार में वर्तमान वैश्विक रुझान
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला की पुनर्संरचना के बीच भारत की स्पर्धात्मकता को बढ़ाना
- भारतीय सौर क्षेत्र
- बजट 2021–22 में कृषि


तिमाही प्रकाशन

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

## विकास सहयोग बढ़ाने के लिए काउंटरट्रेड रणनीति

दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं को भू-राजनीतिक चुनौतियों और तमाम मूल्य श्रृंखलाओं में उनसे संबंधित अनिश्चितताओं के अनुरूप बदलाव करने पड़े हैं। नतीजतन वैश्विक आर्थिक विकास को 2019 की शुरुआत से ही बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई देशों पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। इस महामारी ने विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों को तेजी से प्रभावित किया है, जो विदेशी मुद्रा के लिए मुख्य रूप से प्राथमिक कमोडिटी निर्यातों पर निर्भर हैं। इनमें से कई देश कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण पहले से ही भारी दबाव का सामना कर रहे थे। वैश्विक मांग में कमी आने से ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के राजस्व पर प्रभाव और बढ़ गया। नतीजतन, कई देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अपने मौजूदा राजकोषीय खर्चों में परिवर्तन करना पड़ा है।

मंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों और इनकी बहाली में अनिश्चतताओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई विकासशील देशों के लिए विदेशी ऋण चुकौती एक चुनौती बन गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा फरवरी 2020 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अल्प आय वाले देशों में से लगभग आधे देश (70 में से 36 देश) या तो ऋण संकट के उच्च जोखिम में थे या पहले से ही ऋण संकट में थे।

कोविड-19 के बाद मांग में आई गिरावट और न्यून कमोडिटी मूल्यों के साथ, कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता के चलते इन देशों के लिए ऋण चुकौती दुष्कर होगी। नतीजतन, इन देशों में महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के वित्तपोषक भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा, यदि संकट जारी रहता है तथा देशों पर दबाव बढ़ता है तो आने वाले समय में ऋण की रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ सकती है।

इस पृष्ठभूमि में, ऋणग्रस्त देशों में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए काउंटरट्रेड प्रभावी तरीका है। साथ ही इससे वित्त की कमी का सामना कर रहे देशों को उनके विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्तीय सहयोग भी मिलेगा। यह बकाया की वसूली या संसाधन संपन्न उधारकर्ता देशों से आगामी चुकौतियां सुरक्षित करने का भी प्रभावी तरीका हो सकता है। इनमें वे देश भी शामिल हैं, जहां ऐसे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन हैं, जो भारतीय व्यवसायों को उनकी उत्पादन प्रक्रियाओं में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा, काउंटरट्रेड प्रभावी बाजार विविधीकरण रणनीति के रूप में भी काम कर सकता है, क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों के लिए ऐसे देशों में अवसर खुल सकते हैं, जहां दोहन न्यूनतर रहा है और जो आउटवार्ड रेमिटैंस में प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।

भारत ने अतीत में भी तात्कालिक उपाय के रूप में काउंटरट्रेड का उपयोग किया है। इसलिए भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्थाओं /रियायती वित्तपोषण/क्रेता ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत बकाया की

वसूली और महामारी से प्रभावित ऋणग्रस्त देशों से चुकौती का दबाव कम करने की दृष्टि से काउंटरट्रेड रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। इससे कम दोहित/उच्च जोखिम वाले बाजारों में भारत के परियोजना निर्यातों को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

## काउंटरट्रेड व्यवस्था

काउंटरट्रेड ऐसी व्यवस्था है, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए भुगतान के रूप में धन के बजाय वस्तुओं और सेवाओं का ही लेन-देन किया जाता है। यह व्यापार की पुरातन व्यवस्था है और ऋणग्रस्त देशों के लिए फिर से अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर रही है। काउंटरट्रेड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किन्तु मूल रूप से यह वस्तु विनिमय या अर्ध-वस्तु विनिमय व्यवस्था है जो स्पष्ट रूप से आयात और निर्यात लेनदेन को जोड़ती है। इसमें निजी फर्मों और/या विदेश व्यापार संगठनों जैसी सरकारी संस्थाओं के बीच व्यापारिक व्यवस्था शामिल है, जिसके द्वारा विक्रेता अपने माल (कुछ मामलों में प्रौद्योगिकी या औद्योगिक लाइसेंस जैसी कुछ सेवाएं), विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के निर्यातों के लिए क्रेता से आंशिक रूप से या पूर्ण निपटान के रूप में स्वीकार करने को बाध्य होता है।

वस्तु-विनिमय, काउंटर-खरीद, ऑफसेट, बायबैक (मुआवजा), स्विच ट्रेडिंग, क्लियरिंग व्यवस्था और माल के लिए ऋण जैसे कई अलग-अलग प्रकार के काउंटरट्रेड लेनदेन हैं। इनमें से "माल के लिए ऋण मॉडल" विकासात्मक वित्तपोषण की जरूरत वाले देशों के साथ भारत की संबद्धता के दायरे और बढ़ाने का अवसर देता है। "माल के लिए ऋण" ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कोई ऋणदाता देश फंडिंग उपलब्ध कराने या बकाया ऋण की पूर्ण या आंशिक चुकौती के लिए अपनी वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है।

## काउंटरट्रेड का औचित्य

हालांकि वर्तमान में वैश्विक व्यापार में काउंटरट्रेड व्यवस्था की नगण्य हिस्सेदारी है। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन स्थितियों में लाभप्रद है, जहां मुद्रा आधारित व्यापार व्यवस्था से संबंधित चुनौतियां हैं और जब देशों को घटते विदेशी मुद्रा भंडार का सामना करना पड़ता है।

## अतीत से सीख

काउंटरट्रेड व्यवस्थाओं के मामले में भारत का मिला-जुला अनुभव रहा है। सफलता के साथ-साथ चुनौतियों से भारत को महत्त्वपूर्ण सबक मिले हैं। रुपया-रियाल व्यापार व्यवस्था सहित ईरान के साथ भारत की काउंटरट्रेड व्यवस्था भविष्य की व्यवस्थाओं के लिए टेम्पलेट के रूप में काम कर सकती है। भारतीय और ईरानी व्यवसायों के बीच जानकारी का अभाव, इस व्यवस्था के तहत द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक बाधा थी। इस अभाव को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरा करने की कोशिश की गई, जहां भारत-ईरान व्यापार संबंधी तमाम सूचनाएं प्रदान की गईं और दोनों देशों के क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक ई-बाजार उपलब्ध कराया गया। काउंटरट्रेड व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने और सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के साथ भी ऐसी ही पहलें विकसित करने की जरूरत है।

काउंटरट्रेड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनरों के उत्पादों के लिए परस्पर मांग की भी जरूरत होती है। भारत के अनुभव से दोनों तरफ से आयातों में गिरावट के चलते सामने आने वाली संभावित चुनौतियों का पता चलता है। इसलिए काउंटरट्रेड व्यवस्था में इस तरीके से परिवर्तन की आवश्यकता है कि पार्टनर देशों के बीच काउंटरट्रेड लेनदेन की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। काउंटरट्रेड व्यवस्था के तहत मलेशिया से भारत द्वारा पाम ऑयल के आयातों के कारण घरेलू खाद्य तेल कंपनियों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसलिए, ऐसी व्यवस्थाएं करते समय घरेलू उद्योगों की स्पर्धात्मकता का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके अलावा, विश्लेषण में भारत की ऑफसेट नीतियों पर पुनर्विचार करने और निर्यातों को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण से जुड़े ऑफसेट्स के उपयोग के लिए अवसरों को चिह्नित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। भारत सरकार को अनुपालन सुनिश्चित करने और पर्याप्त सौदा-शक्ति प्रदान करने के लिए ऑफसेट नीति में भी बदलाव करने की आवश्यकता है।

## भारतीय संदर्भ में काउंटरट्रेड व्यवस्था रणनीति

भारत में काउंटरट्रेड रणनीति के दोहरे उद्देश्य हो सकते हैं (i) जरूरतमंद विकासशील देशों को विकास वित्त सहायता प्रदान करना, जिससे अन्य विकासशील देशों में, विशेष रूप से वैश्विक मंदी के दौरान विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की निरंतरता सुनिश्चित हो सके; और (ii) ऐसे देशों में अवसर तलाशना, जहां भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं हैं, लेकिन उनका कम दोहन किया जा सका है और उन्हें विदेशी मुद्रा उपलब्धता में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

### *i* माल के लिए ऋण: व्यापार मॉडल

- ***प्रमुख उत्पाद और बाजार:*** काउंटरट्रेड रणनीति के लिए शुरुआती कदम उन देशों पर फोकस करना हो सकता है, जहां विदेशी मुद्रा के प्रेषण पर प्रतिबंध है और जिन्हें भारत से विकास वित्तपोषण की आवश्यकता है। हालांकि, पारस्परिक रूप से लाभप्रद दीर्घकालिक व्यापार रणनीति वह होगी जो भारतीय उद्योगों को उनकी महत्त्वपूर्ण संसाधन जरूरतें पूरी करने और भारत के लिए मूल्य श्रृंखला संबद्धता बनाने में भी मदद करे। तदनुसार, संभावित काउंटरट्रेड पार्टनर देशों और काउंटरट्रेड व्यवस्था के तहत उन देशों से आयात की जाने वाली संभावित वस्तुओं की सूची तैयार की गई है। इनमें अत्यधिक ऋणग्रस्त देश शामिल हैं, जो भारतीय उद्योगों के लिए महत्त्वपूर्ण संसाधनों-विशेष रूप से खनिज ईंधन, या गैर-ईंधन प्राथमिक वस्तुओं जैसे कृषि उत्पादों और खनिज संसाधनों से भी समृद्ध हैं।

- ***प्रक्रिया का प्रवाह*** : इंडिया एक्ज़िम बैंक, माल के लिए ऋण मॉडल में काउंटरट्रेड से संबंधित व्यवसाय करने के लिए या

तो किसी अलग डिवीजन या सब्सिडियरी के जरिए एक बहु-विषयक टीम को एक मंच पर ला सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, विशेष रूप से एमएमटीसी और एसटीसी जैसे व्यापारिक निकाय भी अन्य काउंटरट्रेड मॉडलों के माध्यम से अवसरों का पता लगा सकते हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहां आर्थिक दृष्टि से ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करना व्यवहार्य हो। इसके अलावा, सरकार भारत से विकास सहायता प्राप्त करने के इच्छुक ऋणकर्ता देशों के साथ काउंटरट्रेड व्यवस्था की संभावना का पता लगा सकती है और उन उत्पादों की संभावित सूची चिह्नित कर सकती है, जिनका उपयोग इस व्यवस्था के तहत किया जा सकता है। पार्टनर देश की सरकार द्वारा उत्पादों को चिह्नित करने के बाद इंडिया एक्ज़िम बैंक उत्पादों की मांग का आकलन कर सकता है और काउंटरट्रेड के लिए भारत तथा विदेश में उस उत्पाद के क्रेताओं से परामर्श कर सकता है।

बहुत मुमकिन है कि ऋणकर्ता सरकार द्वारा काउंटरट्रेड के लिए चिह्नित वस्तुओं की भारत में पर्याप्त मांग न हो। ऐसी स्थिति में, काउंटरट्रेड के लिए स्विच ट्रेड मॉडल और माल के लिए ऋण मॉडल को मिश्रित रूप में अपनाया जा सकता है। स्विच ट्रेडर के रूप में काम करने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक निकाय की सेवाएं ली जा सकती हैं और ऋणकर्ता सरकार निर्धारित मूल्य का माल स्विच ट्रेडर को बेच सकती है। इंडिया एक्ज़िम बैंक को इस माल का भुगतान स्विच ट्रेडर द्वारा किया जा सकता है, जिसका उपयोग ऋणकर्ता देश की ऋण चुकौती के रूप में किया जाएगा।

### *ii* माल के लिए ऋण: निवेश मॉडल

- ***प्रमुख उत्पाद और बाजार:*** अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी जैसे कई क्षेत्र काफी हद तक विभिन्न महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्त्वों पर निर्भर हैं, जो भारत में सीमित मात्रा में हैं और आयात किए जाते हैं। विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन खनिज संसाधनों को बचाए रखना भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। काउंटरट्रेड रणनीति, रणनीतिक खनिजों तक भारत की पहुंच को सुनिश्चित करने में मददगार हो सकती है।

- ***प्रक्रिया का प्रवाह :*** विकास सहायता की जरूरत वाले विकासशील देश अपने ऐसे खनिज साझा कर सकते हैं, जो अभी तक अप्रयुक्त हैं। ऋणकर्ता सरकार या सरकारी एजेंसियां अन्वेषण और खनन के लिए अपनी परिसंपत्तियां प्रस्तुत कर सकती हैं। फिर सरकार या इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा संभावित भारतीय कंपनियों से इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर, कोई भी भारतीय कंपनी इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर विचार कर सकती है और ऋणकर्ता सरकार के साथ वार्ता कर सकती है। इसके बाद निवेश रूट के जरिए माल के लिए ऋण मॉडल व्यवस्था के लिए त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारतीय इकाई द्वारा मेजबान सरकार को देय लाइसेंस शुल्क/ अधिग्रहण की लागत/ राजस्व हिस्सेदारी फंडिंग में सहायक हो सकती है या इसका उपयोग चुकौती के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों के अधिग्रहण के लिए निवेश मार्ग भी अपनाया जा सकता है, जिसके लिए तकनीकी या प्रबंधकीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

  ऋणकर्ता देशों की असमान सौदा-शक्ति, रेंट-शेयरिंग, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धतियों और पर्यावरणीय एवं सामाजिक लागतों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापार रूट के अनुरूप निवेश रूट के माध्यम से चुकौती प्रक्रिया पारस्परिक रूप से परामर्शी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा, इस व्यवस्था को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिग्रहण की शर्तें ऐसी हों कि खनन गतिविधियों से संपोषी विकास को गति मिले और स्थानीय लोग लाभान्वित हों।

### *iii* *काउंटरट्रेड संबंधी विनियम*

3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 23/ 2000-आरबी के जरिए अधिसूचित तथा समय-समय पर संशोधित, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों संबंधी आरबीआई के मास्टर परिपत्र के अनुसार, भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के मूल्य के एवज में भारत में आयातित वस्तुओं के मूल्य के समायोजन से जुड़े काउंटरट्रेड प्रस्तावों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय शर्तों के तहत विचार किया जाता है।

## आगे की राह

काउंटरट्रेड एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें व्यापक व्यवसायों के साथ विभिन्न हितधारकों को शामिल होने की आवश्यकता होती है। काउंटरट्रेड रणनीति की अवधारणा बनाने और परिचालन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है। इस टास्क फोर्स में वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, एसबीआई और यूको बैंक जैसे वाणिज्यिक बैंकों, इंडिया एक्ज़िम बैंक जैसी विकास वित्तीय संस्थाओं और एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों के सदस्य हो सकते हैं। टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आधार पर एक रोडमैप तैयार किया जा सकता है और शुरुआत में काउंटरट्रेड के विकल्प के लिए कुछ देशों को चिह्नित किया जा सकता है। काउंटरट्रेड के परिचालन के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार और आरबीआई के अनुमोदन से अधिकार प्राप्त संस्था के रूप में कार्य कर सकता है। ■

# भारत में डिजिटल विनिर्माण

चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ नए रोजगार और उत्पाद सृजित करने में भी मददगार है और यह संभव हो पाता है, 3डी प्रिंटिंग, कंप्यूटर की मदद से तैयार किए जाने वाले डिज़ाइन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुरूपता, वर्चुअल रिअलिटी, परिष्कृत प्रक्रिया प्रबंधन जैसी कई प्रक्रियाओं की जटिल श्रृंखला के जरिए। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल विनिर्माण कहा जाता है।

*"**भारत में डिजिटल विनिर्माण**" विषय पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) द्वारा गेटवे हाउस के साथ मिलकर किए गए शोध अध्ययन में बताया गया है कि अपने डिजिटल विनिर्माण की गति बढ़ा लेने से भारत किस तरह वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है।*

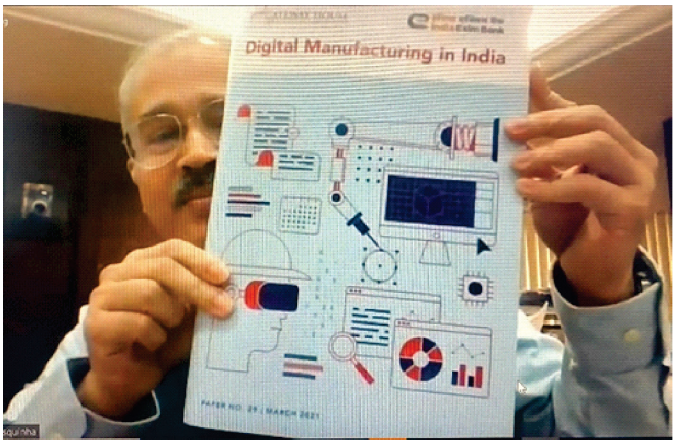


*इस शोध अध्ययन का विमोचन 10 मार्च, 2021 को आयोजित एक ऑनलाइन सम्मेलन में इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना द्वारा किया गया। इस दौरान भारत सरकार और इंडिया इंक के विशिष्ट प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह अध्ययन सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया अभियानों के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है।*

डिजिटल विनिर्माण की परिघटना को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। यह 1990 का दशक था, जब यूएस ने अपने अधिकांश विनिर्माण चीन से आउटसोर्स करना शुरू किया था। लेकिन इसी के साथ सिलिकॉन वैली ने एक बेजोड़ प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकसित किया, जिसके उत्पाद और सेवाएं आज विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का हिस्सा हैं। भारत ने भी विश्व स्तरीय आईटी-सेवा उद्योग बनाया है। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ग्राहक इससे जुड़े हुए हैं। पिछले पांच वर्षों में, भारत ने भी अपनी सरकारी सेवाओं तक लाखों लोगों की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से, खुले स्रोत और सार्वजनिक-निजी प्लैटफॉर्मों का प्रयोग करते हुए शासन और सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया है। इसके साथ ही भारत, चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिजिटलीकृत आबादी वाला देश बन गया है।

भारत में, वैश्विक प्रयासों के समानांतर डिजिटल विनिर्माण की शुरुआत हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए यह आसानी से संभव हो पाया है। ये कंपनियां भारत में अपने परिचालनों के लिए नई प्रौद्योगिकियां ला रही हैं। ओडिशा के कलिंगनगर में टाटा स्टील की इकाई 2019 में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिष्ठित "ग्लोबल लाइटहाउस" में शामिल होने वाली पहली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। यह दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को प्रभावी रूप से एकीकृत किया हो। हाल ही में, दो और भारतीय कंपनियां विश्व आर्थिक मंच के लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल हुई हैं। ये हैं- टाटा स्टील जमशेदपुर और हुबली में रीन्यू पॉवर। यह डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए देश की महत्त्वाकांक्षा और निजी क्षेत्र की क्षमता को दर्शाता है।

भारत में डिजिटल विनिर्माण वास्तव में तभी सफल हो सकता है, जब इसे छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाया जाए। क्योंकि भारत के 90% से अधिक उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। भारत के अधिकांश छोटे और मध्यम उद्यम कम लागत वाले श्रम पर निर्भर हैं और उन्हें डर है कि प्रौद्योगिकी को अपनाना और इस पर निगरानी रखना बहुत महंगा है।

कोविड-19 महामारी ने इस धारणा को बदल दिया है और दुनिया भर में डिजिटलीकरण और डिजिटल विनिर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। भारत इन प्रयासों में प्रमुखता से भागीदारी कर रहा है। जो कंपनियां पहले इसे एक विकल्प के रूप में देखती थीं, वही अब इसे व्यवसाय का अनिवार्य हिस्सा मान कर अपना रही हैं। इस दौरान, भारत में पहले से डिजिटल विनिर्माण के पथ पर अग्रसर ज्यादातर भारतीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने क्रियान्वयन में तेजी लाना शुरू कर दिया है। लंबे समय से चली आ रही डिजिटलीकरण की योजनाओं को लागू करने में महामारी का बड़ा योगदान रहा है। ये योजनाएं दो साल के बजाय अब महीनेभर में ही शुरू हो गई हैं। इनके तत्काल परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

चीन से दूरी बनाते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित परिवर्तन से भारत के लिए डिजिटलीकरण प्रयासों के जरिए विनिर्माण के आधुनिकीकरण की अच्छी संभावनाएं हैं। अपने आकार, बाजार और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को देखते हुए भारत को वैकल्पिक स्थल के रूप में देखा जाता है। हालांकि इससे अब तक कोई तत्काल लाभ नहीं रहा है। शुरुआती चरण में ही इस आशाजनक प्रवृत्ति के मौके को भुनाने के उद्देश्य से सरकार ने नवंबर 2020 में 13 क्षेत्रों को चिह्नित किया है और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इनमें ऑटो और फार्मा जैसे कुछ क्षेत्र विनिर्माण में पहले से ही मजबूत स्थिति में हैं। इनमें दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद भी हैं, जहां अब तक चीन का प्रभुत्व रहा है और भारत को इसमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक-गेटवे हाउस शोध अध्ययन की प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:

- विश्व आर्थिक मंच के "लाइट हाउस नेटवर्क" के समान एक विनिर्माण उत्कृष्टता कार्यक्रम बनाना, ताकि डिजिटलीकरण के लिए भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को चिह्नित किया जा सके।
- छोटे मार्केटिंग बजट में चलने वाले नवोद्यमों की पहुंच बाजारों तक बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं को सरकारी पोर्टल पर व्यवस्थित करते हुए उद्योग 4.0 नवोद्यमों की राष्ट्रीय डायरेक्ट्री का प्रकाशन करना।
- शिक्षण संस्थानों और उद्योगों में तालमेल बढ़ाने के लिए एक ईकोसिस्टम तैयार करना, जिससे कि विनिर्माण उद्योगों के कामगारों और इन-हाउस फैकल्टी में क्षमता विकास किया जा सके।
- भारतीय विनिर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूर्ण डिजिटलीकरण को अपनाना, ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखलाओं में हो रहे वैश्विक परिवर्तन का लाभ मिल सके और भारतीय कंपनियां अपने आप को उद्योग 4.0 के अनुरूप विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर सकें।

भारत में डिजिटल विनिर्माण के लिए ईकोसिस्टम अब दिखाई दे रहा है। यह पश्चिम या चीन की तरह गहन नहीं है, तथापि यह चौतरफा रुप से विकसित हो रहा है। इस ईकोसिस्टम के चार तत्त्व क्रियान्वित हो चुके हैं- डिजिटल बुनियादी ढांचा, सरकारी योजनाएं, अकादमिक शिक्षण और नवोद्यम स्फोट। ■

# भारत–जापान व्यापार संबंध

एशिया में भारत और जापान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। दोनों देश विश्व और विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के साझा हित वाले रणनीतिक पार्टनर हैं। दोनों देशों में राजनीतिक उदारवाद, बाजारवादी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और लोकतंत्र जैसे मूलभूत मूल्य एक समान हैं।

गत कई वर्षों से जापान, भारत के विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक पार्टनरों में से एक रहा है। यह 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता रहा है और भारत के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जापान अपने विदेश मंत्रालय की शाखा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) के जरिए विशेष रूप से बिजली, परिवहन, पर्यावरण परियोजनाओं और बुनियादी मानवीय जरूरतों से संबंधित परियोजनाओं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रयासों में सहायता करता है। दिल्ली मेट्रो ओडीए के जरिए भारत-जापान सहयोग की मिसाल है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), बारह औद्योगिक टाउनशिप्स के साथ दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई-बेंगलूरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) आदि इस सहयोग के हालिया उदाहरण हैं। इन सभी मेगा परियोजनाओं के चालू होने के बाद अगले दशक में भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जापान की ओडीए प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष 2018-19 में 537.4 बिलियन जापानी येन के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर रही थी।

## भारत–जापान व्यापार

भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर 16 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य जापान से भारत को निर्यात किए जाने वाले ऑटो पुर्जों और इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे 90% निर्यातों और जापान द्वारा भारत से कृषि और मत्स्य उत्पादों सहित 97% आयातों पर 2021 तक टैरिफ खत्म करना था। भारत द्वारा किसी भी देश के साथ किए गए करारों में से जापान के साथ सीईपीए सबसे व्यापक व्यापार करारों में से एक है। हालांकि, सीईपीए पर हस्ताक्षर के बाद, भारत और जापान के बीच व्यापार 2010 के 13.1 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2019 में 17.6 अरब हो जाने के बावजूद, भारत से जापान को निर्यात 2019 में भी 2010 के समान ही रहा। वस्तुतः भारत के निर्यातों में 2011-13 के दौरान वृद्धि दर्ज की गई और 2013 में यह निर्यात 7.3 बिलियन यूएस डॉलर के उच्चतम स्तर पर रहा, किन्तु उसके बाद गिरावट के साथ यह सीईपीए के पूर्व स्तर तक आ पहुंचा। भारत से जापान को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, मछली और जलीय अकशेरुकी, प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती रत्न तथा मशीनरी और यांत्रिक उपकरण शामिल हैं। दूसरी ओर, जापान से आयात 2010 के 8.3 बिलियन यूएस डॉलर से लगभग 53% बढ़कर 2019 में 12.7 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। जापान से भारत द्वारा आयात की जाने वाली शीर्ष वस्तुओं में मशीनरी और यांत्रिक उपकरण शामिल हैं। इनके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, लौह एवं इस्पात, प्लास्टिक और तांबा तथा तांबे की वस्तुओं का स्थान है।

नतीजतन, जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बना हुआ है, जो 2009 के 3.5 बिलियन यूएस डॉलर से दोगुने से ज्यादा बढ़कर 2019 में 7.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। जापान से आयातों में तीव्र वृद्धि दर्शाते हुए 2019 में भारत के लिए सबसे ज्यादा व्यापार घाटा दर्ज कराने वाले क्षेत्रों में मशीनरी (3 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का घाटा), इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (लगभग 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का घाटा), लौह एवं इस्पात, प्लास्टिक, तांबा और उसके उत्पाद आदि शामिल रहे।

## भारत की निर्यात क्षमता

उल्लेखनीय है कि जापान के वैश्विक आयातों में भारत ने केवल तीन श्रेणियों में ही अपेक्षाकृत अच्छा हिस्सा (3% से अधिक का) हासिल किया है। ये तीन श्रेणियां हैं- कार्बनिक रसायन, प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती रत्न और मछली तथा अन्य जलीय अकशेरुकी। हालांकि जापान द्वारा अन्य प्रमुख वस्तुओं के आयातों के मामले में भारत की हिस्सेदारी अब भी बहुत कम है। हालांकि भारत में जापान के साथ 3.2 बिलियन यूएस डॉलर की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध के अनुसार, जापान को भारत से खनिज ईंधन और तेल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक उपकरण, दवा उत्पाद, परिधान और कपड़े आदि जैसी श्रेणियों में निर्यातों की अच्छी संभावनाएं हैं।

वर्तमान में जापान को भारतीय निर्यातों के प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें टैरिफ और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय (एसपीएस) जैसी गैर-टैरिफ बाधाएं शामिल हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध "गैर-टैरिफ उपायों पर अध्ययन" में बताया गया है कि भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर जापान में औसत टैरिफ 7% है, जो पूरे देश की साधारण टैरिफ औसत (4%) से कहीं अधिक है।

भारत से जापान को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों जैसे डेयरी उत्पादों, अनाज और इससे तैयार सामग्री, चावल, चमड़ा और जूते, कपड़े और कुछ खाद्य उत्पादों पर टैरिफ बहुत अधिक है। इस प्रकार, आगामी सीईपीए समीक्षा वार्ताओं में, भारत इन उत्पाद श्रेणियों में टैरिफ घटाने का प्रस्ताव रख सकता है। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अपने निर्यातों को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस दिशा में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने व्यापार करारों का अधिकतम लाभ उठाए। ■

# भारतीय कोयला क्षेत्र और कोयला व्यापार में वर्तमान वैश्विक रुझान

## भारतीय परिदृश्य

ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है, जिसका 2019 में वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने में लगभग 27% योगदान रहा है। कोयले के गर्म होने, राख बनने पर तापमान, सल्फर और अन्य अशुद्धियों, यांत्रिक शक्ति और अन्य रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकार होते हैं। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2020 में देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 53.6% कोयले से पूरी हुई। भारत में प्राथमिक ऊर्जा खपत वित्तीय वर्ष 2014 के 25,755 (पेटा जूल्स में) से वित्तीय वर्ष 2019 में बढ़कर 32,453 हो गई, जिसमें 4.7% की सीएजीआर दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान कोयले की खपत में 5.7% की सीएजीआर दर्ज की गई।

**चार्ट 1: प्रमुख स्रोतों से प्राथमिक ऊर्जा खपत में रुझान (पेटा जूल्स में)**

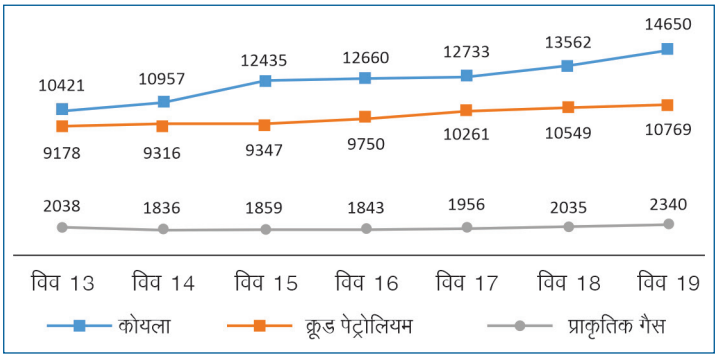


*स्रोत: क्रिसिल रिसर्च*

2019-20 में भारत में कोयले का उत्पादन 729.1 मिलियन टन (एमटी) (अनंतिम) आंका गया था। जबकि 2018-19 में यह 728.7 मिलियन टन था। वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान कोयला उत्पादन में 3.9% की सीएजीआर दर्ज की गई। 2019 में भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश रहा। 2020-21 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान, कोयले के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 3.4% की कमी देखी गई। अप्रैल-जून 2020 (लॉकडाउन अवधि) में मासिक उत्पादन 2019 की इसी अवधि के दौरान मासिक उत्पादन की तुलना में कम रहा। हालांकि, लॉकडाउन खत्म होने के बाद उत्पादन में वृद्धि होने लगी है। सितंबर 2020 के दौरान, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कोयले के उत्पादन में 20.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कोयले का आयात लगातार बढ़ रहा है। 2017-18 के बाद से कुल घरेलू खपत में आयात का हिस्सा बढ़ रहा है। 2016-17 में घरेलू खपत में आयात की हिस्सेदारी 23% थी, जो 2019-20 में 26% आकलित की गई।

**चार्ट 2: घरेलू आपूर्ति और कोयले का आयात (मिलियन टन में)**

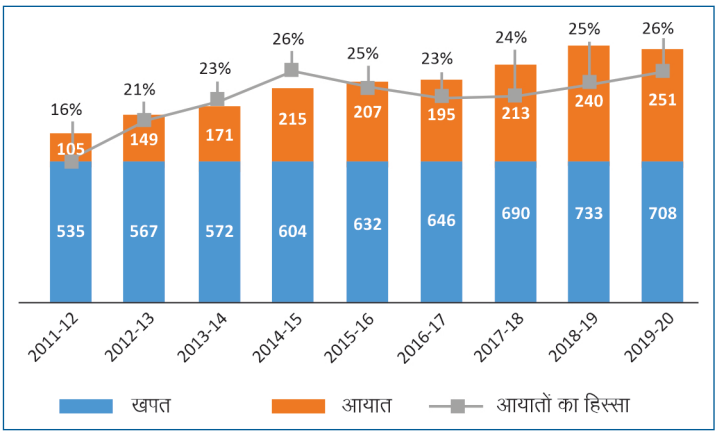


*स्रोत: सीएमआईई इंडस्ट्री आउटलुक, क्रिसिल रिसर्च*

2020-21 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान कोयले के निर्यात में 45.7% की वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में निर्यात के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट रही। तथापि, अगस्त 2020 में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 के दौरान कोयला निर्यात में 102.6% की वृद्धि हुई।

## वैश्विक रुझान और चीन-ऑस्ट्रेलिया गतिरोध का कोयले पर प्रभाव

वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया कोयले का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसने 2019 में 44.4 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया। जापान के बाद चीन, 21.6% की हिस्सेदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया से कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। ऑस्ट्रेलियाई कोयले पर चीन द्वारा हाल ही में लगाए गए आयात प्रतिबंध के कारण ऑस्ट्रेलियाई व्यापार पर काफी असर पड़ने का अनुमान है और ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों ने पहले ही वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों की नए बाजारों की तलाश पूरी होने तक ऑस्ट्रेलियाई धातु उद्योग से जुड़े लगभग 22% कोयला निर्यातों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई कोयले पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही चीन के उद्योगों को भी महंगा कोयला लेना पड़ रहा है। चीन में उच्च ऊर्जा वाले कोयले की कीमतें (जिसे ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है) बढ़ती जा रही हैं। एक ओर, इस पर प्रतिबंध और इसके बाद कोकिंग और थर्मल कोयले की कीमतों में वृद्धि से चीन के कोयला आधारित क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप चीन में उत्पादित अलॉय की कीमतों में वृद्धि से भारत के स्टील निर्माताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई कोयले पर अनिश्चितकालीन

चीनी प्रतिबंध से भारत के लिए कोकिंग कोयले की आयात कीमतें निकट भविष्य में अस्थिर रहने की संभावना है।

2020-21 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान, ऑस्ट्रेलिया से भारत द्वारा कोकिंग कोयले का आयात मूल्य (इकाई विक्रय) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान देखे गए आयात मूल्य (इकाई विक्रय) से कम रहा। इस प्रतिबंध के बाद वैश्विक कोकिंग कोयले की कीमतों में गिरावट इसका संभावित कारण हो सकता है। इससे भारत के कोकिंग कोल आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी और यह प्रतिबंध भारतीय इस्पात उद्योग के लिए लाभकारी होगा।

**चार्ट 3: ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयला आयात की भारत का इकाई विक्रय (₹/टन)**

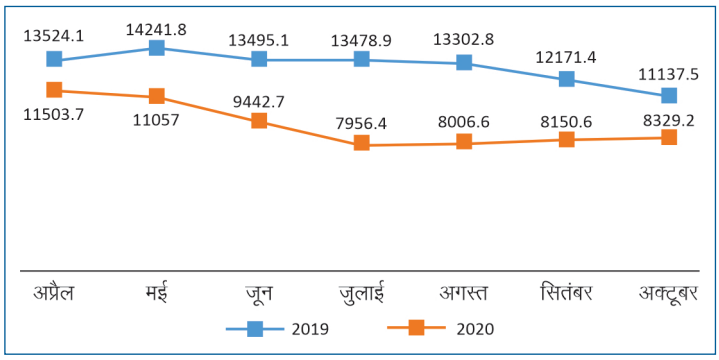


*स्रोत: सीएमआईई इंडस्ट्री आउटलुक*

इस प्रतिबंध का भारतीय इस्पात निर्माताओं पर असर हाल के महीनों में उनकी आय पर भी देखने को मिला है। 2020-21 की पहली तिमाही में इस्पात उद्योग के लिए परिचालन मार्जिन 6.4% था, जो सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में 18.9% रहा। यह दिसंबर 2018 तिमाही के बाद से इस्पात उद्योग में दूसरा सबसे अधिक तिमाही परिचालन मार्जिन था। सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए इस्पात उद्योग के लिए कुल आय के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (पीएटी) जून 2020 तिमाही में -4.3% की दर से बढ़ने के बाद 6.9% आकलित किया गया। कोकिंग कोल की वैश्विक कीमतों में गिरावट से 2021 में ब्लास्ट फर्नेस रूट का इस्तेमाल करने वाली भारतीय इस्पात कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

**चार्ट 4: भारतीय इस्पात उद्योग की कुल आय के % के रूप में तिमाही परिचालन लाभ मार्जिन तथा कर पश्चात लाभ (%)**

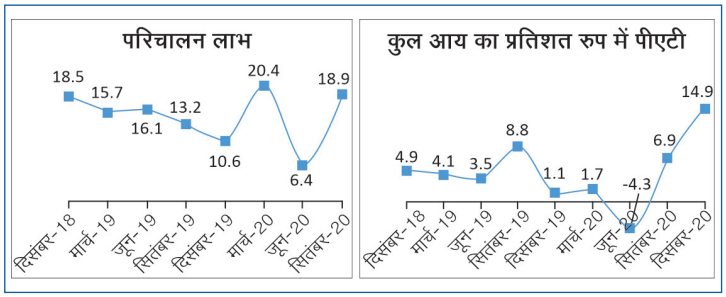


*नोट: दिसंबर 2020 के लिए कर पश्चात लाभ अल्पावधि नमूने पर आधारित है।*

*स्रोत: सीएमआईई इंडस्ट्री आउटलुक*

ऑस्ट्रेलिया से भारत द्वारा कोकिंग कोयले का आयात जून 2020 से (तालाबंदी संबंधी सख्ती कम होने के बाद) बढ़ता रहा है और अक्टूबर 2020 में इसका आयात गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 6.6% अधिक रहा। ऑस्ट्रेलिया से भारत को प्रमुख रूप से कोकिंग कोयले का निर्यात किया जाता है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि मात्रा की दृष्टि से थर्मल कोयले का आयात भी बढ़ रहा है। बहुत मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया से चीन को शिपमेंट न होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई खनिक नए बाजार तलाश रहे हों और भारत के रूप में उन्हें नया बाजार मिल रहा हो। इसलिए भारत द्वारा थर्मल कोयले का आयात बढ़ा हो।

**चार्ट 5: भारत द्वारा थर्मल कोयले का आयात (मिलियन यूएस डॉलर में)**

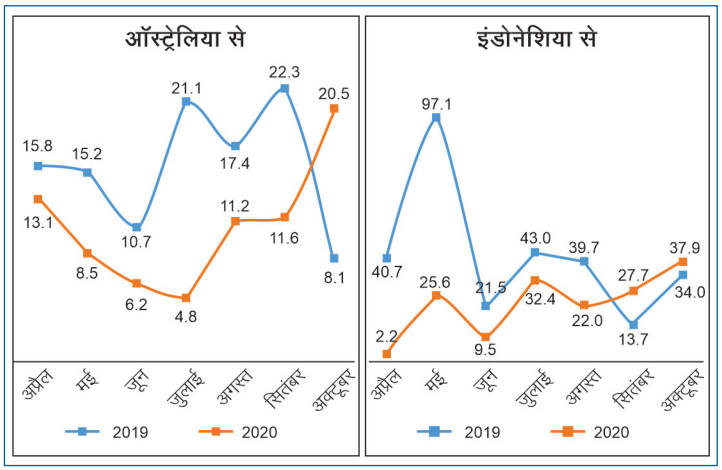


*स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*

**चार्ट 6 : ऑस्ट्रेलिया से भारत द्वारा कोकिंग कोयले का आयात (मिलियन यूएस डॉलर में)**

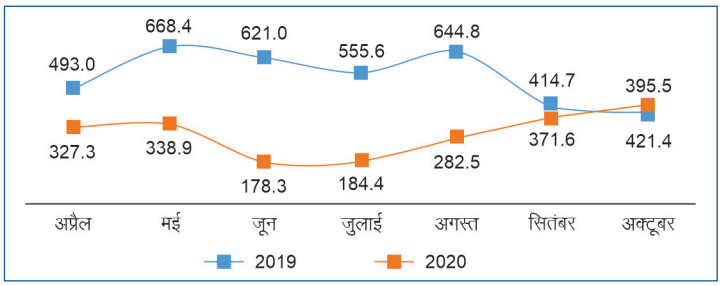


*स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*

भारत में कोयला उद्योग के तिमाही लाभ मार्जिन में उतार-चढ़ाव होता रहा है। जून 2020 तिमाही में यह 56.5% आंका गया था। वहीं, सितंबर 2020 तिमाही में यह 5.8% रहा। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र में अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के दौरान 27.7 मिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई आवक रही। मार्च 2018 में सरकार ने इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी थी। भारत सरकार के अनुसार, 19 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। देश के पांच राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र में देश की पहली वाणिज्यिक खदान नीलामी से सालाना ₹6,656 करोड़ (900.59 मिलियन यूएस डॉलर) का कुल राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। ■

# वैश्विक मूल्य श्रृंखला की पुनर्संरचना के बीच भारत की स्पर्धात्मकता को बढ़ाना

कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बड़ा झटका लगा है। परिणामस्वरूप, इन पर अप्रत्याशित अनिश्चितता बढ़ गई है। एक तो यूएस-चीन व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार संभावनाएं पहले ही कमजोर थीं, ऊपर से इस महामारी ने इसे और हवा दे दी। महामारी से पैदा हुई समस्याओं की वजह से, कई कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने के लिए प्रयासरत हैं और अपनी उत्पादन मूल्य श्रृंखला में किसी एकल या बड़े आपूर्तिकर्ता पर से अपनी निर्भरता को कम करने के उपाय करने में जुटी हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने जोखिमों को कम करने के लिए विकल्प के तौर पर नए निवेश स्थान तलाश रही हैं। इससे भारत जैसे देशों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं में आने वाले नए बदलावों का लाभ उठाने के नए रास्ते निकल आए हैं।

## निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत परिवेश

मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में अनुकूल प्रोत्साहन मिलने के चलते ये अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) का हिस्सा हैं। लेकिन महामारी की वजह से हुई तालाबंदी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वाली बाधाओं के चलते निवेशकों ने अपने निवेश संबंधी फैसले लेते समय स्थानीय बाजार के आकार जैसे अन्य कारकों को देखना भी शुरू कर दिया है।

भारत की प्रतिस्पर्धी ताकत उसके बड़े घरेलू बाजारों में हैं और भारत की यही खासियत घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों को आकर्षित करती है। भारत के निर्यातों में स्पर्धात्मकता अन्य के साथ-साथ भारत में सस्ते श्रम और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, सेवा क्षेत्र में कौशल लाभ जैसे कारकों के कारण है। इसके अलावा, सरकार भारत की निर्यात स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के अनुकूल नीतियां बनाने, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर फोकस करने और व्यवसाय सुगमता में सुधार लाने जैसे विभिन्न कदम उठा रही है। भारत सरकार द्वारा व्यवसाय सुगमता में काफी सुधार किए गए हैं, जिससे विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में भी सुधार आया है। देश की रैंकिंग 2014 में 142वें पायदान से 2019 में 63वें पायदान पर आ गई है।

भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिस्पर्धी निवेश प्रोत्साहन अब तक अपर्याप्त थे, जिसके चलते मूल्य श्रृंखला निवेश स्थान के रूप में उभरने की देश की संभावनाओं को झटका लगा था। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के शुरू होने से भारत के महत्त्वपूर्ण विनिर्माण निवेश केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है। इस योजना से प्रमुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही भारत के विनिर्माण क्षेत्र में स्पर्धात्मकता बढ़ाकर भारत की आयात निर्भरता कम की जा सकती है। अतः, कई पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत अब विभिन्न व्यवसाय परिचालनों के लिए वैकल्पिक केंद्र बनने के लिए अच्छी स्थिति में है।

निर्यात बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत समयानुकूल है, क्योंकि भारत की प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में से एक "भारत से वस्तु निर्यात योजना" (एमईआईएस) 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त कर दी गई है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) जैसी नई योजना सहित पीएलआई योजना देश को निर्यातों के लिए अधिक व्यापक, उत्पादन उन्मुख और डब्ल्यूटीओ के अनुरूप प्रोत्साहन प्रणाली की दिशा में ले जाएगी।

## विनिर्माण में आंतरिक वृद्धि के लिए पीएलआई

आज सेवाओं से लेकर कच्चे माल और पुर्जों तक में लगभग 70% अंतरराष्ट्रीय व्यापार जीवीसी के जरिए होता है। इसलिए, जीवीसी के जरिए निर्यातों को बढ़ावा देने में किसी न किसी वस्तु का आयात अवश्य किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की इस विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, पीएलआई योजना देश में उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों के स्थानीयकरण पर फोकस करती है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में आंतरिक वृद्धि हो सके। इस तरह इसे सामान्यतया आयात विकल्प रणनीति नहीं कहा जा सकता है। पीएलआई भारतीय विनिर्माताओं को उनके वैश्वीकरण के प्रयासों में लाभ पहुंचाने, विनिर्माण क्षेत्र की स्पर्धात्मकता बढ़ाने और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण में मददगार साबित होगी।

**"उभरती नई वैश्विक मूल्य श्रृंखला में निर्यातों के लिए भारत की तैयारी और प्रतिस्पर्धी स्थिति" विषय पर वर्चुअल चर्चा**

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप (एसबीआईएल), कोलकाता के सहयोग से 17 मार्च, 2020 को "उभरती नई वैश्विक मूल्य श्रृंखला में निर्यातों के लिए भारत की तैयारी और प्रतिस्पर्धी स्थिति" विषय पर वर्चुअल पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक, विदेश व्यापार संस्थान; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; और इंडिया एक्ज़िम बैंक के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

# भारतीय सौर क्षेत्र

भारत सौर ऊर्जा संपन्न देश है और इस क्षेत्र में यहां विपुल क्षमताएं हैं, जिनका अब तक दोहन नहीं किया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में करीब 300 दिन गर्मी ही रहती है। नतीजतन, भारत को लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति वर्ष सौर ऊर्जा मिलती है, जो भारत में होने वाली कुल ऊर्जा की खपत से कहीं ज्यादा है।

भारत में 2010 में सौर फोटोवोल्टिक की स्थापित क्षमता मात्र 0.1 गीगावाट थी। 2019 में यह क्षमता बढ़कर 35.0 गीगावाट तक पहुंच गई। अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता में हिस्सेदारी की दृष्टि से देखा जाए तो सौर फोटोवोल्टिक की स्थापित क्षमता 2010 की 1% से बढ़कर 2019 में 27.3% हो गई। भारत में सौर फोटोवोल्टिक द्वारा 2019 में बिजली उत्पादन 30,707 गीगावाट प्रति घंटे दर्ज किया गया, जो 2010 के 65 गीगावाट प्रति घंटे से काफी ज्यादा रहा।

लेकिन 2011 से 2019 के दौरान भारत फोटोवोल्टिक (पीवी) सेलों का निवल आयातक रहा है। इस दौरान व्यापार घाटा भी 1.0 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। इस दौरान, भारत से पीवी सेलों का निर्यात अनियमित रहा और 2019 में 12.9**%** की एएजीआर के साथ यह 277.2 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ, 2019 में इसका आयात 21.5% की एएजीआर के साथ 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

## सौर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां

### *चीन पर आयात निर्भरता कम करना*

पीवी सेलों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। चीन पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माता अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही पीवी सेलों पर मॉड्यूल और सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ाना भी आवश्यक है। इस प्रकार, चीन से सोलर सेल और मॉड्यूल के आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ाने के साथ-साथ एक प्रस्तावित बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने की भी उम्मीद है।

### *घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करना*

सौर पीवी सेल बनाने में कई वस्तुओं का उपयोग होता है। सोलर सेल और मॉड्यूल के निर्माण में सबसे महत्त्वपूर्ण दो चीजें हैं- सिलिकॉन वेफर्स और सिल्लियां। तथापि, भारत के पास इन दोनों के लिए ही विनिर्माण सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए अधिकतर इन्हें चीन से आयात किया जाता है।

भारत सरकार सौर वेफर और सिल्ली विनिर्माण इकाइयां लगाने वाली परियोजनाओं को अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करने पर विचार कर सकती है। वीजीएफ सामान्यतया एकबारगी या आस्थगित अनुदान होता है। यह अनुदान ऐसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को सहयोग के लिए प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से तो न्यायोचित हैं, लेकिन उनमें वित्तीय क्षमता की कमी है। यह वित्त सौर वेफर्स और सिल्लियों के विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

### *निवेश जुटाना*

अक्षय ऊर्जा में निवेश लक्ष्यों को पूरा करने और उनकी क्षमताओं के दोहन के लिए इस क्षेत्र में निवेश को गति देने की जरूरत है। 2010 से 2019 के दौरान भारत के सौर बिजली क्षेत्र में कुल 21.4 बिलियन यूएस डॉलर का पूंजीगत व्यय दर्ज किया गया था। तथापि, 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के केंद्र सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सालाना 36 गीगावाट की क्षमता स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशकों की ओर से पूंजी प्रवाह जरूरी है।

मौजूदा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं के साथ-साथ नई इकाइयों को बढ़ाने के लिए भी निवेश जुटाना महत्त्वपूर्ण है। इस बात को समझना भी महत्त्वपूर्ण है कि नए अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) से होने वाले विनिर्माण सौर उद्योग को आगे बढ़ाएंगे और इसमें तेजी लाने के लिए अनुसंधान और विकास में भी निवेश की आवश्यकता होगी। चीन की तर्ज पर भारत भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ सौर पीवी सेल क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित वित्तीय पैकेज लाने का प्रयास कर सकता है।

### *मेक इन इंडिया के लिए वैश्विक आयातकों को लक्षित करना*

वैश्विक पीवी सेलों के आयात का लगभग 4% आयात भारत करता है। हालांकि, कई और राष्ट्रों में भी सौर सेलों की मांग बहुत ज्यादा है। यूएसए, नीदरलैंड और जापान कुछ ऐसे देशों में शामिल हैं, जिन्हें लक्षित किया जा सकता है।

वैश्विक पीवी सेलों का लगभग 14.3% हिस्सा यूएसए आयात करता है। इसके द्वारा किए जाने वाले आयात का लगभग 33% हिस्सा मलेशिया से आता है, इसके बाद अन्य बड़े आयातकों में वियतनाम (20%) और दक्षिण कोरिया (9.2%) का नाम आता है। नीदरलैंड और जापान का मामला और भी मजबूत है। नीदरलैंड सौर सेलों के वैश्विक व्यापार का लगभग 7% आयात करता है जबकि जापान लगभग 6% आयात करता है। उल्लेखनीय है कि नीदरलैंड और जापान का क्रमशः 63% और 61% आयात चीन से होता है।

भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का ध्वजवाहक रहा है और इन देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ाते हुए सौर सेलों के निर्माण के लिए भारत में इन देशों के संयंत्र स्थापित करने संबंधी आर्थिक समझौते कर सकता है। इससे यह लाभ होगा कि इन देशों के आयात स्रोतों का विविधीकरण हो जाएगा और वे एक या दो स्रोतों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके साथ ही भारत को पीवी सेलों की बढ़ी हुई घरेलू क्षमता का फायदा मिल सकेगा और देश आने वाले समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के लिए पीवी सेलों के निर्माण केंद्र के रूप में भी उभर सकता है।

चूंकि मेक इन इंडिया का उद्देश्य, दुनिया के लिए बनाएं (मेड फॉर वर्ल्ड) भी भी है, इसलिए भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण आधार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, इन राष्ट्रों को भारत में अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए करों में छूट देने जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा इनके साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी समझौते भी किए जा सकते हैं। ■

# बजट 2021-22 में कृषि

केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को कुल ₹1,23,017.57 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष के बजटीय आवंटन ₹1,34,399.77 करोड़ से 8.5% कम है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹1,16,757.92 करोड़ के संशोधित अनुमान से 5.4% अधिक है। मनरेगा के लिए आवंटन को 2020-21 के लिए ₹61,500 करोड़ के बजटीय अनुमान से बढ़ाकर ₹73,000 करोड़ कर दिया गया है। 2020-21 के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजटीय आवंटन ₹75,000 करोड़ से घटाकर ₹65,000 रुपये किया गया है। कुछ राज्यों में इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और कवरेज के लिए अपेक्षित आंकड़ों की उपलब्धता की कमी के चलते यह कटौती की गई है।

मौजूदा बजट में कृषि के बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है। इसके लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के लिए आवंटन को ₹30,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) परियोजनाओं के लेआउट में भी वृद्धि हुई है। इससे ग्रामीण अवसंरचना की वजह से आने वाली अड़चनों और इसकी वजह से कृषि व्यापार के जोखिमों के कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा, जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के व्यापार सहित कृषि व्यापार को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन के लिए आवंटन में वृद्धि का भी अनुमान है। नाबार्ड के तहत ₹5,000 करोड़ की शुरुआती निधि के साथ माइक्रो सिंचाई कोष भी बनाया गया है, जिसे बजट 2021-22 में बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है। कृषि आधारभूत संरचना निधि के लिए ₹900 करोड़ का बजट आवंटन भी किया गया है।

कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) कम वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिनकी सूची निम्नलिखित है:

**तालिका 1: चुनिंदा वस्तुओं पर प्रस्तावित एआईडीसी**

| वस्तुएं | प्रस्तावित उपकर (कस्टम्स) |
|---|---|
| सोना, चांदी और मिश्रित सोना | 2.5% |
| मादक पेय पदार्थ (अध्याय 22 के अंतर्गत आने वाले) | 100% |
| पाम ऑयल | 17.5% |
| सोयाबीन और सूरजमुखी का कच्चा तेल | 20% |
| सेब | 35% |
| कोयला, इग्नाइट और पीट | 1.5% |
| निर्दिष्ट उर्वरक (यूरिया इत्यादि) | 5% |
| मटर | 40% |
| काबुली चना | 30% |
| चने / छोले | 50% |
| तूर दाल (मसूर) | 20% |
| कपास (बिना धुनी / धुनी हुई) | 5% |

ई-नाम के कारण कृषि बाजार में आई पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता को देखते हुए 1,000 अन्य मंडियों को ई-नाम के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे लेनदेन लागत कम करने, किसानों को उनकी फसलों के लिए प्रतिस्पर्धी दाम मिलने और कृषि आय में हुई बढ़ोत्तरी से ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि और संबद्ध उत्पादों और उनके निर्यातों में वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहित करने के लिए, "ऑपरेशन ग्रीन स्कीम" का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। यह योजना वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू जैसे जल्द खराब हो जाने वाले उत्पादों पर लागू है। इसमें 22 अन्य उत्पादों को शामिल करना प्रस्तावित है। इस योजना से किसानों को दो तरह के लाभ होने का अनुमान है। पहला, कीमतों में स्थिरता (अल्पावधि में) और एकीकृत मूल्य श्रृंखला का विकास (दीर्घावधि में)। जल्दी खराब होने वाले ज्यादा उत्पादों को शामिल करने से ज्यादा से ज्यादा किसानों और वस्तुओं को इस योजना के तहत कवर किया जा सकेगा और उन्हें लाभ मिलेगा।

इस बजट में, नदियों और जलमार्गों के किनारे अंतर्देशीय मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केंद्रों को विकसित कर देश के मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। अंतर्देशीय मत्स्यिकी उत्पादकों में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश और समुद्री मत्स्यिकी उत्पादकों में छठा सबसे बड़ा देश है। इन पहलों के जरिए भारत के कृषि और संबद्ध निर्यात में 19.1% की हिस्सेदारी रखने वाले मछली उत्पादन को और बढ़ाने तथा भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। 5 वर्षों के लिए ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ खाद्य उत्पाद निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की भी घोषणा की गई है, जिससे कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने, बर्बादी कम होने, रोजगार सृजन और व्यापार बढ़ने की उम्मीद है।

बजट 2021-22 में इस क्षेत्र में लगभग सभी वर्गों/योजनाओं में वृद्धि हुई है। तथापि, अलग-अलग योजनाओं का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि केन्द्रीय योजनाओं में आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो सरकार की हालिया पहलों अर्थात कृषि निर्यात नीति, कृषि आधारभूत संरचना निधि (एआईएफ) और कृषि कानूनों के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और उनके संवर्धन को शासित करने वाली योजनाओं में आवंटन में पिछले बजट की तुलना में इस बार 180% की वृद्धि देखी गई है। यह हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों में सीमांत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान उत्पादक संगठनों के गठन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के अनुरूप है। इसी तरह एआईएफ के लिए आवंटन में भी पिछले बजट के मुकाबले 333% बढ़ोत्तरी की गई है। एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए भी इस निधि का इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को नियंत्रित करने वाली योजना के लिए भी आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50.7% की वृद्धि की गई है, जो चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना को जारी रखने का संकेत है। नई निर्यात नीति में बागवानी निर्यातों को बढ़ाने पर बल दिया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए आवंटन में 48.2% की वृद्धि की गई है। ■

# इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75% के माल एवं सेवाओं का आयात भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा यथा 22 मार्च, 2021 तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 26.76 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 272 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

## इंडिया एक्ज़िम बैंक ने जनवरी-मार्च 2021 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित 6 ऋण-व्यवस्था करारों पर हस्ताक्षर किए:

i. उज़्बेकिस्तान सरकार को "सामाजिक बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं" के वित्तपोषण के लिए 448 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। यह भारत सरकार की ओर से इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा उज़्बेकिस्तान सरकार को प्रदान की गई पहली ऋण-व्यवस्था है।

ii. एस्वातिनी (स्वाज़ीलैंड) सरकार को "**आपदा बहाली स्थल** (डिजास्टर रिकवरी साइट) **निर्माण परियोजना**" के वित्तपोषण के लिए 10.40 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ, इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से एस्वातिनी (स्वाज़ीलैंड) सरकार को अब तक कुल 68.3 मिलियन यूएस डॉलर की 3 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। एस्वातिनी (स्वाज़ीलैंड) को प्रदत्त इन ऋण-व्यवस्थाओं में स्वाजीलैंड में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क, कृषि विकास और कृषि यंत्रीकरण जैसी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

iii. मॉरीशस सरकार को रक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद के वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ, इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मॉरीशस सरकार को अब तक कुल 764.8 मिलियन यूएस डॉलर की 6 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मॉरीशस सरकार को ये ऋण-व्यवस्थाएं ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसेल, मॉरीशस पुलिस बल के लिए रक्षा उपकरण और वाहनों की खरीद, उन्नयन, सर्विसिंग और रखरखाव संबंधी परियोजना, वाटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट के अधिग्रहण संबंधी परियोजना के वित्तपोषण और विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं, बर्थिंग जेटी और मॉरीशस के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बल के मुख्यालय के भवन के निर्माण के वित्तपोषण के लिए इक्विटी में हिस्सेदारी के लिए प्रदान की गई हैं।

iv. सिएरा लियोन गणराज्य को चार समुदायों के लिए मौजूदा पेयजल सुविधा के पुनरुद्धार और चालू परियोजनाओं के विस्तार के लिए 15 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से सिएरा लियोन गणराज्य को अब तक कुल 168 मिलियन यूएस डॉलर की 5 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। सिएरा लियोन गणराज्य सरकार को प्रदत्त इन ऋण-व्यवस्थाओं में ट्रैक्टरों और बुवाई मशीनों, थ्रेशरों, चावल मिलों, मक्का से छिलका अलग करने वाली मशीनों और कीटनाशक स्प्रे उपकरणों के खरीद के साथ-साथ सिएरा लिओन में मौजूदा सुविधाओं के पुनरुद्धार तथा पेयजल आपूर्ति, ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के लिए नई आधारभूत संरचना के विकास और हाइड्रोलिक्स एवं जल प्रबंधन प्रणाली (सिंचाई) सहित भूमि और बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

v. मालदीव सरकार को रक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार को अब तक कुल 1,290 मिलियन यूएस डॉलर की 4 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मालदीव सरकार को प्रदत्त इन ऋण-व्यवस्थाओं के तहत 485 आवासीय इकाइयों के निर्माण, सड़क विकास, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी और खेलों के लिए बुनियादी ढांचागत विकास जैसी अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

vi. निकारागुआ सरकार को 7.35 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। यह ऋण-व्यवस्था निकारागुआ के मनगुआ में स्थित अस्पताल एंटोनियो लेनिन फॉन्सेका के हाई टेक्नोलॉजी केंद्र के भवन को बदलने और नए उपकरणों की आपूर्ति के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से निकारागुआ सरकार को अब तक कुल 94.98 मिलियन यूएस डॉलर की 5 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। निकारागुआ सरकार को प्रदत्त इन ऋण-व्यवस्थाओं के तहत निकारागुआ में दो विद्युत सबस्टेशनों, कार्लोस फॉन्सेका सबस्टेशन के निर्माण, 95 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और तीन सबस्टेशनों के विस्तार के लिए भारत से उपकरणों की आपूर्ति संबंधी परियोजनाओं सहित ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशन परियोजना के साथ-साथ आल्डो चावर्रिया अस्पताल के पुनर्निर्माण संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

**अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:**

श्री सरोज खुंटिया, महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टावर-1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व) नई दिल्ली 110023,
फोन : +91-11-24607700
ई-मेल: eximloc@eximbankindia.in

# तिमाही गतिविधियां

## इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 2.25% प्रति वर्ष की रिकॉर्ड न्यून दर पर 10 साल के लिए जुटाए 1 बिलियन यूएस डॉलर

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 10 साल के लिए 1 बिलियन यूएस डॉलर का बॉन्ड जारी करते हुए साल की शुरुआत की। भारत से बाहर किसी 10 वर्षीय बॉन्ड के लिए 2.25% की कूपन दर रिकॉर्ड न्यून दर है। बैंक की बैलेंस शीट अधिकांशतः डॉलराइज है और बैंक अंतरराष्ट्रीय ऋण पूंजी बाजारों में सबसे बड़े भारतीय दीर्घावधि ऋण बॉन्ड जारीकर्ताओं में से एक है। इसके बॉन्ड को कासी-सोवरिन बॉन्ड के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग बैंक द्वारा लंबी अवधि के ऋण और निर्यात ऋण-व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय परियोजना निर्यातों तथा विदेशी निवेशों को सहयोग के लिए किया जाता है।

## भारतीय खेल वस्तु उद्योग में है 110 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक की निर्यात क्षमता

भारत से खेल वस्तुओं का निर्यात 2019-20 में 278.9 मिलियन यूएस डॉलर का आंका गया था। "खेल वस्तु उद्योग में निर्यात संभावनाएं" विषय पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) की प्रस्तुति के अनुसार, इस क्षेत्र से 110 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक की संभावनाएं हैं, जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है। इस संभावना को भुनाने के लिए बैंक ने कुछ रणनीतियां भी सुझाई हैं। इनमें प्रमुख बाजारों में विनियामकीय जरूरतें पूरी करने के लिए मानकों, गुणवत्ता और प्रमाणीकरण व्यवस्था में सुधार करना, कच्चे माल और तैयार उत्पादों, दोनों के लिए चीन पर आयात निर्भरता कम करना, पदार्थ विज्ञान और खेल विज्ञान में उन्नत शोध को बढ़ावा देने और निवेश के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित करना, तुलनात्मक रूप से कम दोहन किए गए भौगोलिक क्षेत्रों में बाजार पहुंच बढ़ाने की रणनीतियां बनाना, और खेल वस्तु क्लस्टरों के विकास के लिए बुनियादी ढांचा, नियमित रूप से सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन कर जागरूकता फैलाना और इस क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी जैसी प्रमुख रणनीतियां शामिल हैं।

## इंडिया एक्ज़िम बैक, मालदीव में 2000 आवासीय इकाइयों के वित्तपोषण के लिए देगा 130 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) द्वारा मालदीव के हुलहुमाले में 130 मिलियन यूएस डॉलर की 2000 आवासीय इकाइयों के डिजाइन एवं निर्माण का वित्तपोषण किया जाएगा। इस संबंध में इंडिया एक्ज़िम बैंक और फही दहीरुलन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मालदीव सरकार के बीच 20 फरवरी, 2021 को एक आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) का आदान-प्रदान किया गया। यह फंडिंग राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना के अंतर्गत क्रेता ऋण कार्यक्रम के तहत की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना के जरिए मालदीव के नागरिकों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान होगा और यह भारत सरकार की "पड़ोसी देश प्रथम" नीति (नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी) के अनुरूप है। आशय पत्र का आदान-प्रदान भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के मालदीव दौरे के दौरान माले शहर में किया गया। इस परियोजना का निष्पादन एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

## इंडिया एक्ज़िम बैंक ने मुंबई की महिला पुलिस कर्मियों के सम्मान में की "प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर्स" पहल

कोरोना वायरस महामारी के चलते हम सभी को असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। मुंबई जैसे महानगर में रोज़मर्रा की बेशुमार चुनौतियों के बावजूद, मुंबई पुलिस कोरोना योद्धाओं के रूप में अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी जान की सुरक्षा में बिना थके और बिना रुके डटी रही। 08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंडिया एक्ज़िम बैंक ने "प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर्स" पहल की और इसके तहत मुंबई की 900 महिला पुलिस कर्मियों को ऑर्गेनिक शहद भेंट किया। बैंक ने ये शहद अंडर द मैंगो ट्री प्राइवेट लिमिटेड (यूटीएमटी) से लिया है। यूटीएमटी एक सामाजिक उद्यम है, जिसे बैंक द्वारा ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत सहयोग प्रदान किया गया है।

## डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया के लिए नया लक्ष्य: डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग

कोविड-19 महामारी के चलते, पूरी दुनिया में डिजिटल क्षेत्र में तेज़ी आई है और इसमें भारत की मुख्य भागीदारी रही है। चीन से दूरी बनाते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित परिवर्तन कर भारत अपने डिजिटलीकरण प्रयासों के जरिए विनिर्माण को आधुनिक बना सकता है। "भारत में डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग" विषय पर प्रोग्रेसिव पॉलिसी इन्स्टीट्यूट,वॉशिंगटन डीसी के सहयोग से भारतीय निर्यात-आयात बैंक(इंडिया एक्ज़िम बैंक) द्वारा गेटवे हाउस के साथ मिलकर किए गए इस शोध अध्ययन में बताया गया है कि अपने डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की गति बढ़ा लेने पर भारत किस तरह वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है।

## भारत को अपनी व्यापार नीति को और अधिक उदार बनाने की जरूरत: प्रो. अरविंद पनगड़िया

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाले दुनियाभर के विद्वतजन भारत की व्यापार नीति पर विमर्श के लिए शुक्रवार, 19 मार्च, 2021 को एक मंच पर आए। यह मंच था, इंडिया एक्ज़िम बैंक के 36वें स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान का। यह व्याख्यान कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और इंडियन पॉलिटिकल इकनॉमी के जगदीश भगवती प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया द्वारा दिया गया। व्याख्यान का विषय था- भारत की व्यापार नीतिः कल आज और कल। प्रो. पनगड़िया ने भारत की व्यापार नीति के ऐतिहासिक पहलू प्रस्तुत करते हुए कहा कि आजादी के समय भारत ने आत्मनिर्भर होने की नीति को चुना और इसी नीति के जरिए भारत ने यह तय किया कि हमें अपने उत्पादों को दुनिया के दूसरे बाजारों में बेचने और अपनी जरूरत का सामान दूसरे बाजारों से खरीदने की बाध्यता से आजाद होना है। यह लक्ष्य इस मकसद से रखा गया ताकि ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण किया जा सके, जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियों में राज्य की महती भूमिका हो और निजी निवेशों का आवंटन राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाए, न कि लाभ के अवसरों को ध्यान में रखकर; और यही लक्ष्य इसे आर्थिक अक्षमता की ओर ले गया। ■

# विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

## तुर्की

तुर्की की अर्थव्यवस्था 2020 में 0.4% की दर से बढ़ी। 2020 की पहली दो तिमाहियों के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। किन्तु, तीसरी तिमाही में ब्याज दरें गिरने और ऋण देने में आई तेजी के चलते 19.1% की दर से आर्थिक सुधार देखने को मिला। मुद्रास्फीति दर 2019 की 15.2% से गिरकर 12.3% रही, लेकिन यूएस डॉलर और यूरो के मुकाबले लीरा में गिरावट के चलते यह उच्च स्तर पर बनी रही। 2021 के दौरान मजबूत वैश्विक मैक्रोइकनॉमिक परिवेश से निर्यातों में वृद्धि और निर्यात मांग बढ़ने के चलते देश की अर्थव्यवस्था के 4% की दर से बढ़ने के आसार हैं। 2021 में मुद्रास्फीति भी कम होने की उम्मीद है और मुद्रास्फीति दर गिरकर 11.1% रह सकती है। तथापि यह तुर्की के केंद्रीय बैंक के आधिकारिक लक्ष्य 5% से काफी अधिक है। अधिक मुद्रास्फीति मुख्य रूप से वैश्विक खाद्य और कमोडिटी के बढ़ते मूल्यों के कारण है। 2021 में लीरा में थोड़ी और गिरावट आने की आशंका बनी रहेगी और इसके एक यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 7.3 के स्तर पर बने रहने के आसार हैं। चालू खाता घाटा 2020 में जीडीपी का 5.5% रह सकता है और 2021 में अर्थव्यवस्था के पुनः संतुलित होने से इसके तेजी से गिरकर जीडीपी के 1.9% रहने की उम्मीद है।

## जापान

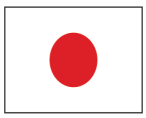

जापान की जीडीपी 2020 में 4.8% की गिरावट के बाद 2021 में कोविड महामारी के कुछ कम होने और निजी खपत तथा विदेश व्यापार में बढोत्तरी की उम्मीदों के बीच 2.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तथापि, खपत का स्तर 2025 तक महामारी से पूर्व वाले स्तर पर आने के आसार नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति कम होने से पारिश्रमिक वृद्धि भी कम होती है। मुद्रास्फीति 2021 में 0.2% रहने के आसार हैं। हालांकि वैश्विक तेल कीमतों और औद्योगिक उत्पादों तथा शिपिंग की लागत के बढ़ने से उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। 2021 में वैश्विक व्यापार में सुधार होने से जापान की वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ने की उम्मीद है। जापान ने मशीनरी, रोबोटिक्स और सेमिकंडक्टर उद्योग स्थापित किए हैं। औद्योगिक ऑटोमेशन और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की रीस्ट्रक्चरिंग से इन उत्पादों की मांग बढ़ेगी। जापानी येन 2021 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर सालाना औसतन 105.6 येन रहने के आसार हैं। जापानी येन में मजबूती जापान का शीर्ष ऋणदाता देश का दर्जा बने रहने और चालू खाते में सरप्लस के चलते बनी रहेगी। 2021-25 की अवधि के दौरान देश में चालू खाता सरप्लस बने रहने की उम्मीद है, जो जीडीपी के औसतन 3.3% के समतुल्य होगा।

## क़तर

कोविड-19 महामारी और तेल और गैस के दामों में गिरावट के चलते क़तर की वास्तविक जीडीपी 2020 में 3% की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें 2019 में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह क़तर की वास्तविक जीडीपी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट रही। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और तेल के न्यूनतर दामों के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रा अवस्फीति 2019 की 0.9% की तुलना में 2020 में 2.6% रही। क़तर से प्रतिबंध हटने से 2021 में आर्थिक गतिविधियों में कुछ तेजी आने की उम्मीद है। तथापि, वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम ही बनी रहेगी, क्योंकि तेल और गैस के दामों में मामूली वृद्धि की ही उम्मीद है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2021 में 2.5% तक होने की उम्मीद है, क्योंकि मुल्क को चीन के साथ-साथ एलएनजी की वैश्विक मांग बढ़ने की उम्मीद है। निजी खपत में तेजी आने से मुद्रास्फीति दर 2021 में औसतन 0.6% रहने की उम्मीद है। रियाल का मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले 3.64 रहा, जो मुल्क के राजकोषीय और विदेशी ऋण संतुलन को प्रदर्शित करता है। उम्मीद की जा रही है कि क़तर विशेष रूप से उभरते बाजारों को प्रभावित करने वाले मौद्रिक दबाव और पूँजी निकालने से पड़ने वाले प्रभावों से तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में रहेगा।

## ब्राज़ील

वर्ष 2020 में 4.3% की गिरावट की मार झेलने वाली ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में, कोविड-19 का टीका आने और इस महामारी के नियंत्रण में आने की उम्मीद के बीच 2021 में 3.2% की वृद्धि दर के साथ आंशिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं। तथापि, अर्थव्यवस्था के 2022 तक महामारी से पूर्व वाले स्तर पर आने के आसार नहीं हैं। मूल्य दबाव न्यून रहने के आसार हैं और मुद्रास्फीति दर में 2021 के लिए निर्धारित लक्ष्य (3.8%), 2022 (3.5%) और 2023 (3.3%) के निम्न मध्यम बिंदु के आसपास उतार-चढ़ाव होते रहने की संभावना है। तथापि, यदि सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में रियायत बरतने के प्रति प्रतिबद्ध रहती है तो मुद्रास्फीति दर बढ़ सकती है। 2020 में रियाल के मूल्य में करीब 22% की गिरावट आई और यह एक यूएस डॉलर के मुकाबले 5.2 के स्तर पर बंद हुआ। गिरती आर्थिक उम्मीदों और राजकोषीय जोखिम के चलते बाजार में गिरावट के कारण रियाल के मूल्य में अभी और गिरावट की आशंका बनी हुई है। तथापि, ब्राजील की व्यापार शर्तों, ब्याज दरों में अंतर और वैश्विक जोखिम मूल्यांकन के अनुरूप उतार-चढ़ाव के बीच रियाल के 2025 तक एक यूएस डॉलर के मुकाबले कुछ मजबूत होकर 4.85 के स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। 2020 में कुछ कम होने के बाद ब्राजील के आयातों में वृद्धि की उम्मीद के बीच 2021-2025 ते दौरान चालू खाता घाटा कुछ बढ़ने की आशंका है और यह 2025 में जीडीपी का 3.4% रह सकता है। हालांकि, 2021-25 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी औसतन 3.6% के स्तर पर इसके लगभग समतुल्य रहने की उम्मीद है। ■

# मुद्रा की प्रवृत्तियां

## यूरो

€ यूएस डॉलर के मुकाबले यूरो मजबूत रहा है और 06 जनवरी, 2021 को 1.2349 के वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर रहा था। हालांकि यूरो जनवरी-फरवरी के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत रहा, लेकिन फरवरी के अंत से इसमें गिरावट शुरू हो गई। यूरो और यूएस डॉलर अब तक ऋणात्मक रूप से सहसंबंधित रहे हैं।

इस ऋणात्मक सह संबंध के संकेत अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की बढ़ी हुई संभावनाओं और कमजोर यूरो के साथ मार्च 2021 में मिले थे। उसके बाद यूएस डॉलर मजबूत हुआ है और बढ़त पर है।

फरवरी के अंत में एक यूएस डॉलर के मुकाबले यूरो 1.2242 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। किन्तु इसके बाद से इसमें गिरावट जारी रही। 19 मार्च, 2021 को यूरो एक यूएस डॉलर के मुकाबले 1.1903 के स्तर पर बंद हुआ।

## कानाडाई डॉलर

C$ कनाडा की अर्थव्यवस्था में आश्यचर्यजनक रूप से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यहां के व्यवसायों को इस वर्ष अच्छी रिकवरी की उम्मीद है और वे इन्वंटरी जमा कर रहे हैं। ओट्टावा में स्टैटिस्टिक्स कैनेडा द्वारा जारी प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, चौथी तिमाही में जीडीपी 9.6% रही। यह ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए 7.3% के मध्यावधि पूर्वानुमान से तीव्रतर है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी गिरावट का सामना करने के बाद आंकड़े गवाह हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ने लॉकडाउन की अंतिम लहर से कितने अच्छे तरीके से निपटा है और इसमें कितना लचीलापन है, जो 2021 में संभावनाओं के सहारे बेहतर वर्ष की उम्मीद में है। 04 जनवरी, 2021 और 19 मार्च, 2021 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर क्रमशः 1.2777 और 1.2597 पर बंद हुआ।

अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा सहारा लगातार दो तिमाहियों तक स्टॉक ड्रॉ-डाउन करने के बाद इन्वेन्टरी स्तर के पुनर्निर्माण करने वाले व्यवसायों से मिला, जिसे कंपनियों द्वारा मांग बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इससे उपभोक्ता खर्च के लिए बेहद कमजोर रहे वर्षांत से हुई हानि को कम करने में मदद मिली, जिसमें कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते अप्रत्याशित रूप से गिरावट दर्ज की गई थी।

गत वर्षांत में हुई वृद्धि में सरकारी खपत और रियल एस्टेट बाजार से संचालित आवासन में निवेश का भी बड़ा योगदान रहा।

## दक्षिण अफ्रीकी रैंड

R कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को पिछले वर्ष संभवतः सदी की सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। 2020 कैलेंडर वर्ष में यहां की अर्थव्यवस्था में 2019 की 0.2% तुलना में 7% की गिरावट आई। यह 1946 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रही। 2020 की अंतिम तिमाही में जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष 4.1% की गिरावट आई, जो उससे पिछली तिमाही में 6.2% की गिरावट की तुलना में थोड़ी कम रही।

कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से यूएस डॉलर के मुकाबले दक्षिण अफ्रीकी रैंड में गिरावट जारी रही। 04 जनवरी, 2021 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले दक्षिण अफ्रीकी रैंड 14.7149 के स्तर पर रहा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से यह दोबारा प्रभावित हुआ।

वैश्विक अर्थिक सुधार की गति को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निवेशकों की भावनाओं से संकेत लिया और मार्च के प्रथम सप्ताह से यूएस डॉलर और दक्षिण अफ्रीकी रैंड में दो महीनों में हुई हानि में कुछ सुधार देखने को मिला। 19 मार्च, 2021 को दक्षिण अफ्रीकी रैंड का मूल्य प्रति यूएस डॉलर 14.7003 रहा। बाजार से संचालित आवासन में निवेश का भी बड़ा योगदान रहा।

## दक्षिण कोरियाई वॉन

₩ दक्षिण कोरियाई वॉन एक यूएस डॉलर के मुकाबले 19 मार्च, 2021 को 1,129.12 पर बंद हुआ, जो 04 जनवरी, 2021 को 1,086.48 के स्तर पर था। प्रथमदृष्ट्या, दक्षिण कोरियाई वॉन में गिरावट कुछ अनियमित-सी प्रतीत होती है। एक तरफ जोखिम-वहन क्षमता बढ़ रही है और दूसरी तरफ मुद्रा में गिरावट हो रही है।

वैश्विक भावनाओं में उतार-चढ़ाव के प्रति अति संवेदनशील वॉन गत वर्ष की शुरुआत से यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 5% तक गिर चुका है। यह वैश्विक वृद्धि की बलवती संभावनाओं के बीच अपनी समतुल्य उभरती एशियाई मुद्राओं की तुलना में कमजोर पड़ रहा है।

निधियों का प्रवाह इसके कारण पर कुछ प्रकाश डालता है। घरेलू निवेशक जनवरी में नेट 6.2 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी बॉन्ड और स्टॉक खरीदे। कोरिया सिक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी के आंकड़ों के अनुसार यह 2011 से रिकॉर्ड निवेश है। विदेशी मुद्रा मैनेजरों ने भी जनवरी के आखिरी सप्ताह में नेट 5.3 बिलियन यूएस डॉलर के स्थानीय स्टॉक ऑफलोड किए, जो 1999 के बाद से सबसे बड़ा आउटफ्लो है।

विपुल तरलता (लिक्विडिटी) और रियल एस्टेट के सख्त विनियमों के चलते घरेलू निवेश विकल्पों में कमी आने से धन देश से बाहर जा रहा है। तथापि, दक्षिण कोरिया की मुद्रा में यह गिरावट ट्रांजिटरी हो सकती है, क्योंकि वैश्विक निधियों के इस देश के इक्विटी बाजार में लौटने की संभावना है। ■

# एक्ज़िम मित्र

*भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और व्यापार वित्त, ऋण बीमा सुविधाओं तथा भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार संबंधी अन्य जानकारियों की उपलब्धता में विषमता को कम करने के लिए एक्ज़िम बैंक ने एक्ज़िम मित्र नाम के एक पोर्टल की शुरुआत की। एक्ज़िम मित्र निर्यातों के लिए ऋण की उपलब्धता और व्यापार संबंधी जानकारी देने के दोहरे उद्देश्य के साथ काम करता है। एक्ज़िम मित्र भारतीय उद्यमियों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मिलने वाले सवालों को हल करने में मदद करता है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:*

## डाक के जरिए ई-कॉमर्स निर्यात के लिए प्रक्रिया

निर्यातों को सुगम बनाने और भारत के निर्यातकों को विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के जरिए वैश्विक फलक पर स्थापित करने के क्रम में, सभी आईईसी धारकों को विदेशी डाकघर (एफपीओ) के जरिए वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है। एफपीओ के जरिए वस्तुओं का निर्यात करने वाला कोई भी आईईसी धारक, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के रिफंड या वचन पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) की चुकौती के जरिए शुल्कमुक्त निर्यात के लिए पात्र है। डाक के जरिए ई-कॉमर्स निर्यातों को शामिल करने के क्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने "डाक द्वारा निर्यात विनियम, 2018" के अंतर्गत घोषणा पत्र निर्धारित किए हैं। निर्यातक निर्यातों का पोस्टल बिल (पीबीई) फाइल कर वस्तुओं के साथ एफपीओ में कस्टम्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्यातकों के परिचालनों को सुगम बनाने के लिए कस्टम ब्रोकरों को भी सभी विदेशी डाकघरों में अनुमति प्रदान की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कस्टम ब्रोकरों / निर्यातकों (पीबीई स्वयं फाइल कराने के लिए) को एफपीओ में परिचालन शुरू करने से पहले थर्ड-पार्टी वेब ऐप्लिकेशन को ऑनबोर्ड करना जरूरी होता है। यह ऐप्लिकेशन निर्यातक और कस्टम ब्रोकरों के बीच संचार को सुगम बनाने, शिपमेंट में पारदर्शिता बनाने और पीबीई प्रिंट करने या बी2बी उपयोग के लिए किन्हीं अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।

## विदेशी प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में वस्तुओं की बिक्री संबंधी प्रक्रिया

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी / व्यापार मेले में प्रतिभागियों को फेमा विनियम, 2000 के विनियम 7(7) के जरिए विदेश में अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। निर्यातक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी / व्यापार मेले में अपनी वस्तुओं की बिक्री से हासिल विदेशी मुद्रा को यहां जमा करा सकते हैं और उस समय भारत से बाहर रहने के दौरान उस खाते का परिचालन कर सकते हैं, बशर्ते कि उस खाते में जमा राशि को सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिए प्रदर्शनी / व्यापार मेले की समाप्ति के एक महीने के अंदर वापस भारत वापस भेजा जाए और इसका संपूर्ण विवरण प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों को प्रस्तुत किया जाए।

## रजिस्ट्रेशन-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) निर्यात संवर्धन परिषदों या भारत में कमोडिटी बोर्डों द्वारा पांच वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। यह इस प्रमाण के रूप में जारी किया जाता है कि कोई निर्यातक परिषद/बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। किसी प्रतिबंधित वस्तु के आयात / निर्यात हेतु प्रमाणीकरण के लिए आवेन करने वाला कोई व्यक्ति या विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जैसे लाभ लेने वाले व्यक्ति के लिए डीजीएफटी को इसकी वेबसाइट पर आयातक निर्यातक प्रोफाइल में आरसीएमसी प्रस्तुत या अपलोड करना जरूरी होता है। आरसीएमसी हासिल करने के लिए निर्यातक को एएनएफ2सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद / कमोडिटी बोर्ड में आवेदन दाखिल करना होता है। अपने उत्पाद के लिए निर्यात संवर्धन परिषद / कमोडिटी बोर्ड की जानकारी के लिए निर्यातक एक्ज़िम मित्र पोर्टल पर निर्यात आयात की जानकारी खंड में निर्यात संवर्धन निकाय खंड देख सकते हैं।

## विदेशी कार्यालयों से भारत में धन प्रेषण संबंधी विवरण

आवर्ती व्ययों के लिए गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री / आय या टर्नओवर का 10% रेमिटैंस नियम और शर्तों के अनुसार, विदेश स्थित कार्यालय (ट्रेडिंग/नॉन ट्रेडिंग)/ शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के सामान्य व्यवसाय परिचालन के लिए भेजा जा सकता है। इसके लिए विदेश स्थित कार्यालय को भुगतान जारी करने के लिए एडी बैंक से आवेदन किया जा सकता है।

## भारत से मांस निर्यात संबंधी जानकारी

डीजीएफटी की अनुसूची-2 निर्यात नीति के अनुसार, चिल्ड और फ्रोजन मांस के निर्यात की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि निर्यातक निर्यात के समय कस्टम्स को उससे संबंधित वैध एपीडा संयंत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां और यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करे कि उपर्युक्त को एपीडा से पंजीकृत एकीकृत बूचड़खाने या एपीडा से पंजीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्र से लिया गया है, जहां कच्चा माल एपीडा से पंजीकृत बूचड़खाने से ही मंगवाया जाता है। ■

# आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

## वस्तु व्यापार

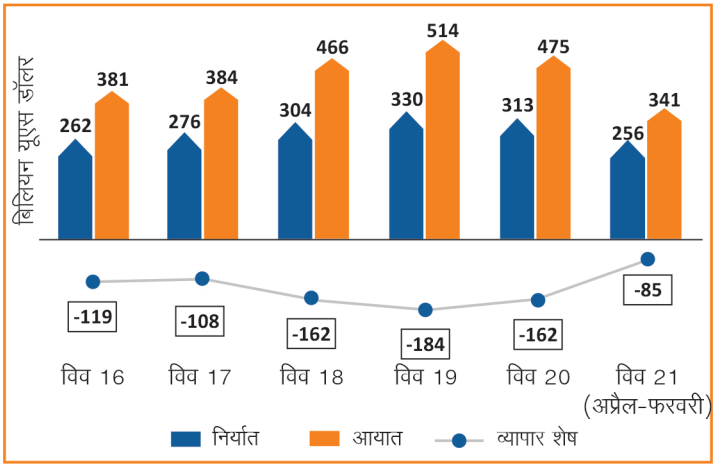


*स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार*

## सेवा व्यापार

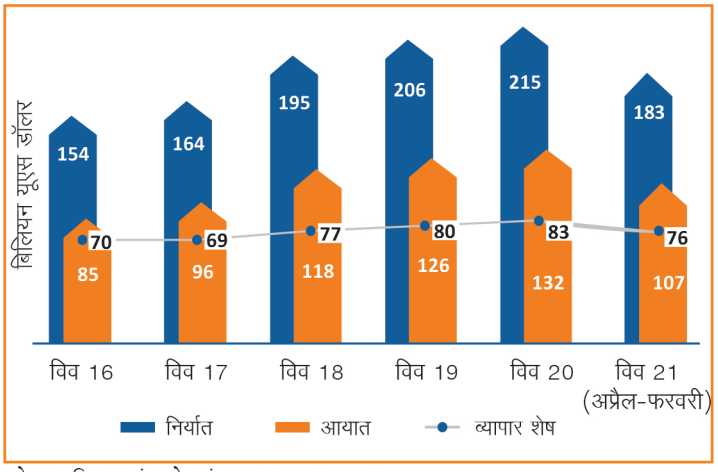


*स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार*

## प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

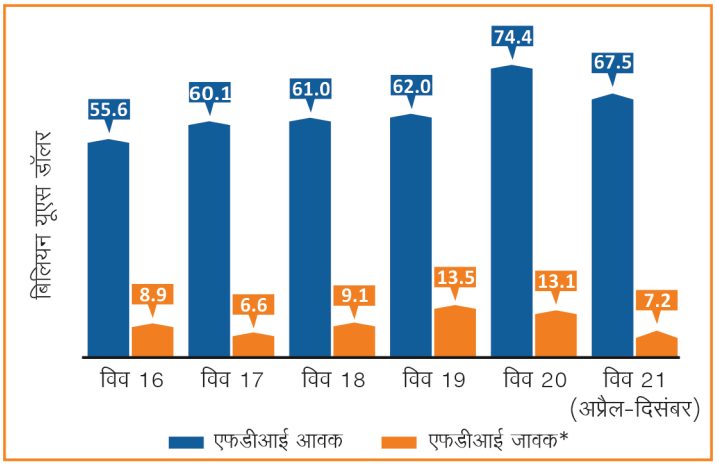


*नोट:* - एफडीआई जावक में इक्विटी, ऋण और इन्वोक की गई गारंटियां शामिल हैं।*
*स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार*

## उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

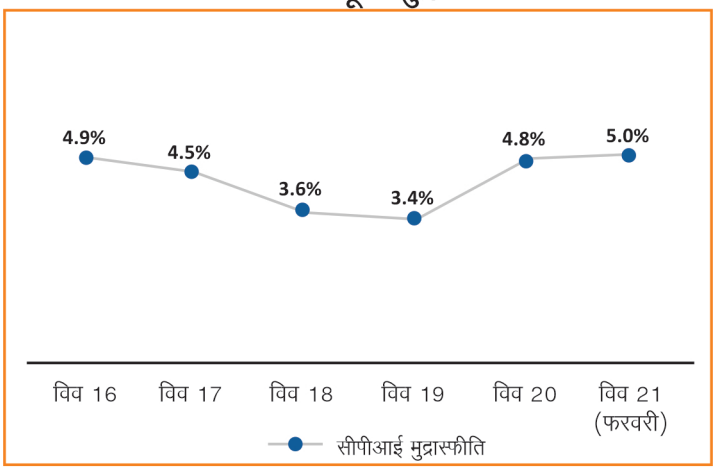


*स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार*

## चालू खाता घाटा

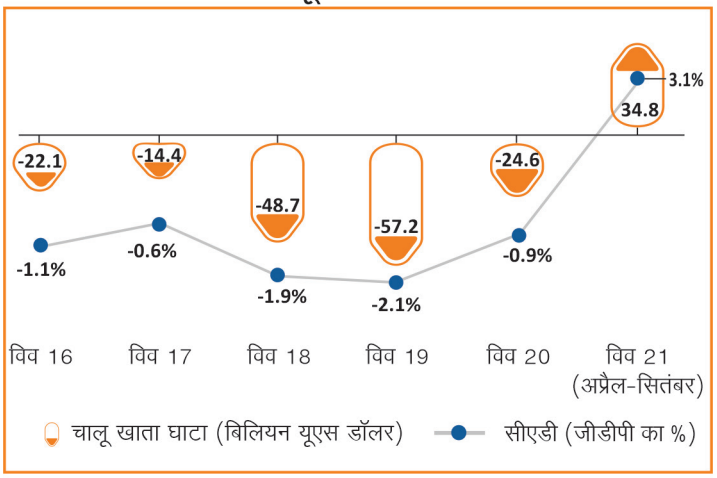


*स्रोत: आरबीआई*

## क्षेत्रवार उत्पादन

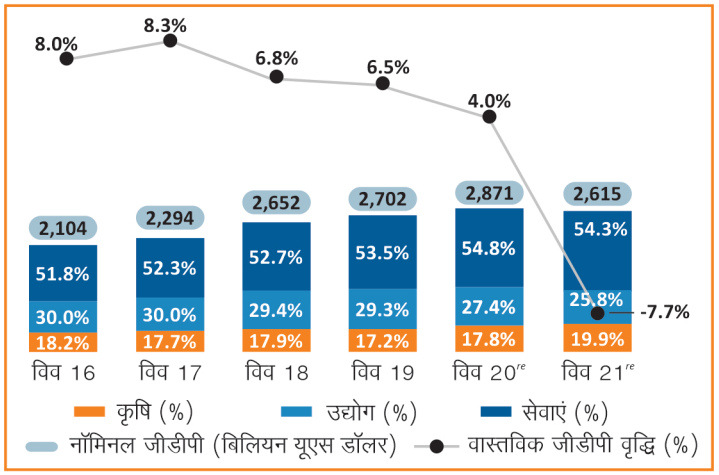


*नोट: re- संशोधित पूर्वानुमान; ae- अग्रिम पूर्वानुमान*
*स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार और आरबीआई*